पूर्ण न्यायपीठ

माननीय न्यायमूर्ति

एम आर अग्निहोत्री, आर एस मोंगिया और बी एस नेहरा, जे जे।

मिस चेतना शर्मा और अन्य-याचिकाकर्ता।

बनाम

संघ क्षेत्र, चंडीगढ़ और अन्य,-उत्तरदाता।

1991 की सिविल रिट याचिका संख्या 11995

5 सितंबर, 1991

भारत का संविधान,* 1950-अनुच्छेद *226-पंजाब* विश्वविद्यालय *अधिनियम, 1947-धारा 27,* 30 *और* 31-खिलाड़ियों के लिए सीटों *का आरक्षण-पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ प्रवेश के लिए अपने स्वयं के* मानदंड निर्धारित कर *सकता है-मूल्य-खेलों* में *उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले एक से अधिक उम्मीदवार-प्रवेश विद्या सम्बन्धी श्रेष्ठता पर आधारित होना चाहिए-खिलाड़ियों के श्रेणीकरण का एक समान स्वरूप अपनाना।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां तक खिलाड़ियों/महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियों को वर्गीकृत करके उनकी श्रेणीकरण का संबंध है, प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे राजेश कौशिक बनाम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ *और अन्य* 1990 (*एस. एल. आर. 658)* के मामले में इस न्यायालय द्वारा पहले ही जारी किए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करें और तदनुसार खिलाड़ियों/महिला खिलाड़ियों के लिए आरक्षित कोटे के अनुसार सीटों पर दाखिले करें।चूंकि राजेश कौशिक के मामले में एकल पीठ के फैसले को पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा जा चुका है, इसलिए इसमें जारी किया गया श्रेणीकरण के समान स्वरूप को अपनाने का निर्देश चंडीगढ़ प्रशासन के साथ-साथ उनके द्वारा संचालित पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ के लिए भी बाध्यकारी हो जाता है।

(पैरा 9 & 12)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां तक पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर में निहित पंजाब विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों की प्रयोज्यता का संबंध है, पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 की धारा 27 और 31 में संबद्धता आदि के लिए शर्तें निर्धारित करते हुए विस्तृत

विनियम बनाए गए हैं, लेकिन खिलाड़ियों/महिला खिलाड़ियों के लिए सीटों के आरक्षण या संबद्ध कॉलेजों में दाखिले के समय उन्हें महत्व देने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।इसलिए, यह तर्क कि केवल इसलिए कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़, पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध है, यह छात्रों के दाखिले के लिए अपने मानदंड निर्धारित नहीं कर सकता है और चंडीगढ़ प्रशासन के शिक्षा और तकनीकी विभागों के नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य नहीं कर सकता, पूरी तरह से बिना किसी आधार के है।किसी भी कल्पना के बिना, एक विश्वविद्यालय राज्य द्वारा संबद्ध कॉलेजों को यह निर्देश देने की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकता है कि खिलाड़ियों/खिलाड़ियों के लिए इतनी सीटें आरक्षित की जाएंगी और यदि ऐसा नहीं किया गया तो संबद्धता को वापस लिया जा सकता है और निर्देशों का पालन न करने के कारण संस्थान को असंबद्ध कर दिया जा सकता है।

(पैरा 13 & 14)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि तकनीकी महाविद्यालयों में दाखिले के मामले में, चयन में एक विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों में से किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए, *यह* निर्धारित करने के लिए अनिवार्य रूप से केवल शैक्षणिक योग्यता पर निर्भर होना चाहिए जैसा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने पी. *सबिता बनाम चिकित्सा शिक्षा निदेशक और अन्य 1983 सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 9406* में 6 अप्रैल, 1984 को निर्णय लिया और *खालिद हुस्साम (नाबालिग) बनाम तमिलनाडु सरकार के आयुक्त और सचिव, स्वास्थ्य विभाग, मद्रास आदि 1987 (4) एस. एल. आर. 098* मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया। इसलिए, पंजाब-इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ द्वारा अपनाए गए मानदंडों के खिलाफ आक्षेप, कि दाखिले उम्मीदवारों के विद्या सम्बन्धी प्रदर्शन महत्व देकर किए जाएंगे, खारिज किए जाने के योग्य हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से उचित और न्यायसंगत है।

(पैरा 15 &16)

खालिद हुसैन (नाबालिग) बनाम *तमिलनाडु सरकार के आयुक्त और सचिव, स्वास्थ्य विभाग, मद्रास, आदि। 1987 (4)* एस. *एल.* आर. 098

(पालन किया)

ध्यान दें:—इस निर्णय *के* खिलाफ *1991 के एस. एल. पी. सं. 15553/91 को सर्वोच्च न्यायालय ने 7 जनवरी, 1992 को निम्नलिखित आदेश पारित करके खारिज कर दिया था।*

"पक्षकारों की विद्वान अधिवक्ता सुनने के बाद।हम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं और उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई वैध आधार नहीं पाते हैं।विशेष अनुमति याचिका तदनुसार खारिज कर दी जाती है।"

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका में अनुरोध किया गया है कि मामले का पूरा रिकॉर्ड मंगवाया जाए:—

I खिलाड़ियों/महिला खिलाड़ियों के लिए आरक्षित सीटों में छात्रों की अंतर-श्रेणी के प्रवेश और मूल्यांकन के उद्देश्य से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपनाए गए मानदंडों को रद्द करते हुए सरशियोरेराई प्रकार की एक रिट जारी किया जाए;

II पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार और 1990 (5) एस. एल. आर. पृष्ठ 658 के रूप में रिपोर्ट किए गए इस माननीय न्यायालय के फैसले के अनुपालन में खिलाड़ियों-पुरुषों/महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर दखिले करने के लिए प्रतिवादी परमादेश प्रकार की एक रिट जारी की जाए।

III उत्तरदाता पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रत्येक शाखा में खिलाड़ियों को 5 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद विभिन्न शाखाओं में सीटें भरने का निर्देश दिया जाए और विभिन्न शाखाओं को सीटें आवंटित करने के मनमाने मानदंड को रद्द कर दिया जाए।

IV इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में यह माननीय न्यायालय कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करे जो उसे उचित लगे;

V उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के तहत प्रतिवादी को अग्रिम नोटिस जारी करना तिरस्कृत किया जा सकता है;

VI अनुलग्नक की प्रमाणित प्रतियों को दायर करना तिरस्कृत किया जा सकता है;

VII याचिका का खर्च कृपया याचिकाकर्ताओं को दिया जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पी. एस. पटवालिया, अधिवक्ता के साथ जी. एस. गिल और एच. एस. सेठी अधिवक्ता

अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ जी. एस. संधवालिया और मनीष जैन, अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति एम आर अग्निहोत्री

1. यह रिट याचिका (1991 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1195) तीन अन्य सी. डब्ल्यू. सं. 1991 के 12052,10758 और 12072 .. के साथ प्रस्ताव पीठ द्वारा स्वीकार के बाद पूर्ण पीठ को निर्देश दिया

गया था कि एक तरफ, इस न्यायालय के एकल पीठ के फैसले जिसे बाद में इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा खारिज किए गए और दूसरी ओर एकल पीठ के फैसले जो उपरोक्त खण्ड पीठ के फैसले पर ध्यान दिए बिना कुछ अलग दृष्टिकोण रखता है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया के बीच संघर्ष, यदि कोई हो, को सुलझा लिया जाए। हालांकि, बारीकी से जांच करने पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा निर्धारित कानून अभी भी क्षेत्र में है, और एकल पीठ का निर्णय जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है, खण्ड पीठ के फैसले के साथ बिल्कुल भी टकराव में नहीं आता है, क्योंकि उसमें एक बहुत ही सीमित और पूरी तरह से अलग प्रश्न पर मामले का फैसला किया था।चूँकि इन याचिकाओं में कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न शामिल हैं, इसलिए उनका निपटान एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है।हालाँकि, इसमें शामिल मुद्दों की सराहना के लिए, 1991 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 11995 से तथ्य लिए गए हैं।

2. केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन, प्रतिवादी संख्या 1, केंद्र शासित प्रदेश में एक इंजीनियरिंग कॉलेज चलाता है, जिसका नाम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ है।वास्तव में यह विभाजन से पहले पंजाब के पंजाब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाहौर (जिसे पहले मदलगन इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था) का उत्तराधिकारी संस्थान, जो 1947 में देश के विभाजन के परिणामस्वरूप पाकिस्तान में बना रहा।यह महाविद्यालय पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से संबद्ध है।सत्र 1991-92 के लिए कॉलेज के विवरण पत्रिका के अनुसार, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए कुल 310 सीटें हैं, जिनमें से पांच प्रतिशत, यानी 16 सीटें खिलाड़ियों/खिलाड़ियों-महिलाओं के लिए आवंटित की गई हैं।इन 16 सीटों को आगे निम्नानुसार श्रेणीवार वितरित किया गया है

Sr. No.	Category	Aero	Civil	Elect.	Elect-ronics	Met.	Prod.	Total
7	Sportsmen/ Women	1	3	1	3	3	5	16

हालांकि, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाता है, फिर भी चंडीगढ़ प्रशासन और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ ने खेल के क्षेत्र में उम्मीदवारों की उपलब्धि के आधार पर खिलाड़ियों/महिलाओं के लिए आरक्षित पांच प्रतिशत सीटों के लिए प्रवेश के लिए अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किए हैं।इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और उम्मीदवारों की संबंधित

योग्यताओं का आकलन करने के लिए मनमानेपन और भेदभाव के तत्व को समाप्त करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, विश्वविद्यालय या जिला स्तर पर उनके प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का श्रेणीकरण खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त विभिन्न पदों को वर्गीकृत किया गया है।महाविद्यालय की विवरणिका में दिए गए दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं:—

"खेलों में उपलब्धि के आधार पर आरक्षित श्रेणी की पांच प्रतिशत सीटों में प्रवेश के लिए दिशानिर्देश। प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटों का पाँच प्रतिशत इस श्रेणी के तहत आरक्षित है।इस श्रेणी में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं करने वाले उम्मीदवारों को खेल के आधार पर कोई महत्व नहीं दिया जाएगा।

3. इस श्रेणी के तहत प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को इस आरक्षित कोटे से प्रवेश के लिए केवल उन खेलों और विषयों में उपलब्धि के आधार पर माना जाएगा जिन्हें विवरण पत्रिका में शामिल किया गया है और केवल तभी जब ये उपलब्धियां प्रवेश के वर्ष से पहले के तीन वर्षों में से किसी में भी विश्वविद्यालय की गतिविधि से संधित हों।

7. व्यक्तिगत खेल विषयों के मामले में, श्रेणीकरण के लिए व्यक्तिगत आयोजनों में पद को माना जाएगा न कि समग्र रूप से टीम की स्थिति के लिए।

8. छात्रों की आपस में योग्यता का निर्धारण पैरा 16 में दिए गए सूत्र का पालन करते हुए उनके जी. ई. टी. स्कोर के 10 प्रतिशत तक वेटेज जोड़कर किया जाएगा, न कि केवल खेल में उनकी योग्यता के आधार पर।

9.आरक्षित श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले उम्मीदवारों के महत्व को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित तरीके से (संलग्नक II में शामिल खेलों/विषयों में खेलों में उपलब्धियों के आधार पर) इस श्रेणी में उनकी योग्यता को तय करना होगा।

"श्रेणी-आई. पी. (अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी):10%

श्रेणी ए प्रमाणपत्र धारक:6%

श्रेणी बी प्रमाणपत्र धारक (स्थान 1,2 और3) :4%

श्रेणी बी प्रमाणपत्र धारक (4-12):3%

श्रेणी सी प्रमाणपत्र धारक 2 प्रतिशत

ध्यान दें —सीधा श्रेणी में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को यह महत्व नहीं दिया जाएगा।

10. इस आरक्षित श्रेणी में प्रवेश के लिए खेल/विषयों में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त वाले खिलाड़ियों की प्रवेश के लिए, जो विवरण-पत्रिका में शामिल नहीं हैं, नियम 5 के तहत गठित समिति द्वारा जो प्रशासक के सलाहकार की अनुमोदन के लिए गृह सचिव को इसकी अनुशंसा करेगा।

खिलाड़ियों के लिए ग्रेडिंग - आई.पी. वर्ग ((अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी)

1. ओलंपिक खेलों/विश्व खेलों/राष्ट्रमंडल खेलों/विश्व कप प्रतियोगिताओं/एशियाई खेलों में पहले तीन स्थानों में से कोई भी स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति।
2. उपरोक्त खेलों/प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति।
3. विदेशों में और देश के भीतर आधिकारिक टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति।

श्रेणी 'ए'

1. राष्ट्रीय प्रतियोगिता/अंतर-राज्य/अंतर-क्षेत्रीय प्रतियोगिता/पूर्व-एशियाई खेलों में पहले तीन स्थानों में से कोई भी स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति।

2. विदेशों में और देश के भीतर वरिष्ठों के लिए अखिल भारतीय संयुक्त विश्वविद्यालय टीमों में शामिल एक व्यक्ति।

3.अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में पहले तीन स्थानों में से कोई भी स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति।

4. अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में और देश के भीतर जूनियर के लिए राष्ट्रीय टीमों में शामिल एक व्यक्ति।

5. विदेशों में और देश के भीतर जूनियरों के लिए अखिल भारतीय संयुक्त विश्वविद्यालय टीमों में शामिल एक व्यक्ति।

6. अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय क्षेत्रीय बैठकों और राष्ट्रीय क्षेत्रीय बैठकों में पहले तीन पदों में से कोई भी प्राप्त करने वाला व्यक्ति।

7. जूनियरों के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पहले तीन पदों में से कोई भी प्राप्त करने वाला व्यक्ति।

8. देश और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्कूलों के लिए राष्ट्रीय टीमों में शामिल एक व्यक्ति।

9. स्कूलों के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पहले तीन स्थानों में से कोई भी प्राप्त करने वाला व्यक्ति।

श्रेणी 'बी'

1.अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में पंजाब विश्वविद्यालय की टीम में शामिल एक व्यक्ति।

2.वरिष्ठ राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की टीमों में शामिल व्यक्ति।

3.पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के अलावा विश्वविद्यालय की अन्य टीमों में अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में शामिल एक व्यक्ति।

4. पंजाब विश्वविद्यालय/अंतर-महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में पहले तीन स्थानों में से कोई भी स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति।

5. वरिष्ठों के लिए अंतर जिला/केंद्र शासित प्रदेश चैंपियनशिप इंमें पहले तीन स्थानों में से कोई भी स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति।

6. पंजाब विश्वविद्यालय के अलावा विश्वविद्यालय अंतर-कॉलेजिएट प्रतियोगिताओं में पहले तीन पदों में से कोई भी प्राप्त करने वाला व्यक्ति।

7. राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की जूनियर टीमों में शामिल व्यक्ति।

8. राष्ट्रीय खेलों में राज्य के स्कूलों/केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों की टीमों में शामिल व्यक्ति।

9. राष्ट्रीय विद्यालय खेलों में सी. बी. एस. ई. (केंद्रीय विद्यालय संगठन) में शामिल एक व्यक्ति।

10. राज्य कनिष्ठ/केंद्र शासित प्रदेश चैम्पियनशिप में पहले तीन पदों में से कोई भी प्राप्त करने वाला व्यक्ति।

11. राज्य विद्यालय/केंद्र शासित प्रदेश खेलों में पहले तीन स्थानों में से कोई भी स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति।

12. सी. बी. एस. ई. (केंद्रीय विद्यालय संगठन) प्रतियोगिता में पहले तीन पदों में से कोई भी स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति।

श्रेणी 'सी

1. आवासीय विश्वविद्यालय में प्रथम तीन पदों में से कोई भी प्राप्त करने वाला व्यक्ति।

2. विश्वविद्यालय "बी" डिवीजन टूर्नामेंट में प्रथम तीन पदों में से कोई भी प्राप्त करने वाला व्यक्ति।

3. सी. बी. एस. ई. (केंद्रीय विद्यालय संगठन) क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में पहले तीन पदों में से कोई भी प्राप्त करने वाला व्यक्ति।"

3.पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त मानदंडों के अनुसार प्रवेश दिए जाने से पहले, याचिकाकर्ताओं ने इसे विभिन्न आधारों पर चुनौती देते हुए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जो कि मनमाना, भेदभावपूर्ण है, जो पंजाब सरकार द्वारा राज्य में अपने संस्थानों के लिए निर्धारित

मानदंडों के विपरीत है, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के अन्य संस्थानों के लिए निर्धारित मानदंड से भी अलग है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ इस अदालत द्वारा पहले के मामले में बनाए गए मानदंडों के विपरीत है।

4. जवाब में, चंडीगढ़ प्रशासन-प्रतिवादी संख्या 1 के साथ-साथ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ के प्राचार्य, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अलग-अलग लिखित बयान दायर किए गए हैं।दोनों प्रतिवादी ने दलील दी है कि माननीया उच्चतम न्यायालय और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा श्रेणीकरण का तरीका निर्धारित किया गया है।यह भी कहा गया है कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा शासित है और खिलाड़ियों/खिलाड़ियों के लिए सीटों के आरक्षण के संबंध में निर्णय और जिन मानदंडों और तरीकों से उन्हें भरा जाना है, वह प्रशासनिक प्रकृति का मामला है जो गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन के निर्णय द्वारा नियंत्रित और विनियमित है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध है, लेकिन यह केवल विद्या सम्बन्धी मामले हैं_जिनके बारे में कॉलेज पंजाब विश्वविद्यालय के नियमों से बंधा है।सटीक रूप से, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य-उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा दायर लिखित बयान के पैरा 7 में लिया गया प्रतिवादी का रुख इस प्रकार हैः—

"प्रतिवादी महाविद्यालय द्वारा अपनाए गए मानदंड न्यायसंगत, कानूनी और खालिद हुसैन के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप हैं, जहां यह उल्लेख किया गया था कि जहां उम्मीदवार कमोबेश बराबर हैं, योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार जाना है सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे मामले में, चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता पर निर्भर करेगा जो उनके पक्ष में एक झुकाव कारक के रूप में सेवा में लगाया जाएगा। प्रतिवादी कॉलेज द्वारा अपनाए गए मानदंड खिलाड़ियों को उनके संबंधित खेलों और विषयों में खेल में उपलब्धि के आधार पर विभिन्न श्रेणियों, यानी ए, बी और सी पैटर्न में विभाजित करते हैं। फिर प्रत्येक श्रेणी को अंकों का विशिष्ट वेटेज मिलता है जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों की कुल संख्या में जोड़ा जाता है। इसलिए, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को 10 प्रतिशत वेटेज मिलेगा जबकि एक राष्ट्रीय खिलाड़ी (वरिष्ठ) को 6 प्रतिशत वेटेज मिलेगा। इसलिए, यह पैटर्न बहुत ही निष्पक्ष और उचित है और उसी उद्देश्य और कारण को बढ़ावा देता है जिसके लिए इसे निर्धारित किया गया है।"

(5) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री पी.एस. पटवालिया ने निम्नलिखित तर्क उठाकर उत्तरदाताओं द्वारा अपनाए गए मानदंडों पर हमला किया: -

(1) पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर में शामिल पंजाब विश्वविद्यालय के नियम और विनियम सभी संबद्ध कॉलेजों पर बाध्यकारी हैं; इसलिए, विश्वविद्यालय कैलेंडर में प्रवेश के लिए निर्धारित

मानदंड पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ द्वारा भी अपनाए जाने चाहिए थे, क्योंकि यह कॉलेज भी पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध है। संबद्ध कॉलेजों द्वारा अपनाए गए मानदंड एक समान होने चाहिए थे और चूंकि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ ने एक समान मानदंड अपनाने में विचलन किया है, इसलिए लिया गया निर्णय मनमाना और भेदभावपूर्ण है।

2. चूंकि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने *राजेश कौशिक बनाम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ और अन्य* में *एकल पीठ 1990 (5) एसएलआर 658* के फैसले में कहा है कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को एकरूपता बनाए रखने के लिए समान मानदंडों को अपनाना चाहिए, इसलिए प्रतिवादी का विपरीत निर्णय इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत है, विशेष रूप से *जब राजेश कौशिक* के मामले (उपरोक्त) के फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है।

3. *रणहिर सिंह बनाम थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला ए. आई. आर. 1988 पी एंड एच 51 मामले में इस अदालत के खण्ड पीठ के फैसले और* एक अन्य (2) ने उम्मीदवारों को उनके खेल श्रेणीकरण प्रमाणपत्रों को महत्व देने की नीति को बरकरार रखते हुए एकल पीठ के फैसले सुश्री *मनिंदर कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य ए. आई. आर. 1981 पी एंड एच 46* को गलत तरीके से खारिज कर दिया है। इसलिए, सुश्री मनिंदर कौर के मामले (ऊपर) में एकल *पीठ के फैसले में* स्वीकार किए गए मानदंडों को प्रतिवादी द्वारा बरकरार रखा जाना और उनका पालन किया जाना चाहिए।

4. पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ द्वारा प्रवेश के उद्देश्य से खिलाड़ियों/खिलाड़ियों का वर्गीकरण मनमाना है और राजेश कौशिक के मामले (उपरोक्त) में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों को *अपनाया जाना चाहिए* और तदनुसार प्रवेश दिए जाने चाहिए।

5. निशानेबाजी के खेल और अनुशासन को खेल श्रेणीकरण और खिलाड़ियों/महिलाओं की आरक्षित श्रेणी में आने वाली सीटों के खिलाफ प्रवेश के उद्देश्य से शामिल किया जाना चाहिए था।

6. यह कि खेल श्रेणी में सीटों का आवंटन इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में होना चाहिए, यानी प्रत्येक शाखा में 5 प्रतिशत सीटें, और इसके विपरीत निर्णय जो इसे केवल इंजीनियरिंग की कुछ शाखाओं तक सीमित रखता है, मनमाना था और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

6. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर कार्रवाई करने के बजाय, बहस *संख्या* 4,5 और 6 को पहली बार में निपटाया जाता है।जहां तक आरक्षित श्रेणी के खिलाड़ियों/महिलाओं के खिलाफ प्रवेश के उद्देश्यों के लिए 'निशानेबाजी' के खेल/अनुशासन को शामिल नहीं करने के खिलाफ शिकायत का संबंध है, हम इसे पहली बार में पूर्ण पीठ द्वारा निर्णय

का विषय नहीं मानते हैं और इस कारण से, निर्देश देते हैं कि 1991 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 10758 (निश्चल गुप्ता बनाम यू. टी. *चंडीगढ़ और अन्य) को 11 सितंबर, 1991* को निर्णय के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए, जो सूची में सबसे ऊपर है।

7. इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में खेल श्रेणी में सीटों के आवंटन के संबंध में, चंडीगढ़ प्रशासन के साथ-साथ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ का इरादा स्पष्ट रूप से इंजीनियरिंग की प्रत्येक शाखा में 5 प्रतिशत सीटें प्रदान करना प्रतीत होता है।न तो कोई निर्णय है और न ही हम इस आशय का कोई इरादा जुटा सकते हैं कि इस आरक्षण को केवल एक निश्चित निर्दिष्ट_शाखाओं तक ही सीमित रखा जाए और न ही इस प्रस्ताव के संबंध में प्रतिवादी के लिखित बयान में कोई गंभीर विवाद उठाया गया था।फलस्वरूप, इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में खेल श्रेणी में सीटों का आवंटन प्रत्येक शाखा में सीटों का 5 प्रतिशत का अंश या पूर्णांक करना होगा।यदि किसी भी शाखा में खेल श्रेणी की कोई भी सीट खाली रहती है, तो इसे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए खुला रखा जाएगा।

8. खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों और महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करते हुए यह उल्लेख किया जा सकता है कि यह मामला पहले याचिकाकर्ता राजेश कौशिक द्वारा 1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 1002 में इस अदालत के समक्ष लाया गया था, जिन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित सीटों के खिलाफ चार वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश का दावा किया था।*राजेश कौशिक बनाम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ और अन्य,* में इस अदालत के एकल पीठ के फैसले में, इस अदालत ने पाया कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ द्वारा खेल श्रेणीकरण के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया था, जबकि पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध अन्य कॉलेजों ने पंजाब सरकार के खेल विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों को अपनाया था।एकरूपता के लिए और मनमाने ढंग से श्रेणीकरण से आने वाले किसी भी प्रतिकूल परिणाम से बचने के लिए, यदि अपनाया जाता है, तो इस न्यायालय ने पंजाब इंजीनियर कॉलेज, चंडीगढ़ को निर्देश दिया कि वह खिलाड़ियों/खिलाड़ियों के लिए वही श्रेणीकरण अपनाए जो अन्य संबद्ध कॉलेजों द्वारा अपनाया गया था।इसलिए, इस न्यायालय द्वारा यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः—

"न्यायाधीशालय द्वारा निर्णय के लिए प्रश्न यह नहीं है कि खेलों में श्रेणीकरण के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए कौन सा प्राधिकरण सक्षम है, अर्थात पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार या पंजाब विश्वविद्यालय, लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ द्वारा अपनाया गया मानदंड प्राकृतिक न्यायाधीश और निष्पक्ष खेल के सिद्धांतों के अनुसार है और वास्तविक उद्देश्य को बढ़ावा देना चाहता है जिसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटें उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित हैं, या यह मनमाना, तर्कहीन या विकृत है।जहाँ तक "उत्कृष्ट" श्रेणी का

संबंध है, यह एक खिलाड़ी को "ओलंपिक खेलों/विश्व खेलों/राष्ट्रमंडल खेलों/विश्व कप टूर्नामेंट/एशियाई खेलों में पहले तीन स्थानों में से कोई भी प्राप्त करने के लिए" प्रदान किया जाता है। यह मानदंड असाधारण है।ग्रेड ए के संबंध में भी यही स्थिति है, जो एक खिलाड़ी को 'राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/अंतर-क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं/पूर्व-एशियाई खेलों में पहले तीन पदों में से कोई भी प्राप्त करने के लिए' प्रदान किया जाता है।लेकिन जहां तक अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में पंजाब विश्वविद्यालय की टीमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, या वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की टीमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, या अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के अलावा विश्वविद्यालय की टीमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जैसा कि 'ग्रेड बी' का संबंध है, प्रत्यर्थी-कॉलेज का निर्णय निश्चित रूप से तर्कहीन और मनमाना है।इसे परिवर्तित परिपथ को ध्यान में रखना चाहिए।खेल के क्षेत्र में भी स्थिति और उसे वर्गीकरण या श्रेणीकरण का पालन करना चाहिए जो समय के प्रवाह के साथ अप्रचलित हो गया है।इस संबंध में, याचिकाकर्ता तकनीकी/चिकित्सा संस्थानों और सरकारी सेवा में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण के संबंध में हरियाणा सरकार के मुख्य *सचिव* द्वारा 7 फरवरी, 1989 को जारी किए गए अपने परिपत्र संख्या बी-2 जी. एस. आई. द्वारा जारी निर्देशों पर दृढ़ता से भरोसा करने के लिए सही है।इस परिपत्र के अनुसार, 18 अक्टूबर, 1972 के पहले के परिपत्र के पैरा 3 को बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए संशोधित किया गया था, जो इस प्रकार हैः

"' 2.3. सरकार ने निर्णय लिया है कि अच्छे और औसत प्रकार के खिलाड़ियों के बीच अंतर आदेश के लिए ए, बी, सी और डी स्तर के प्रमाणपत्रों में अधिक ग्रेड बनाए जाने चाहिए और ऐसा आदेश के लिए, ऊपर उल्लिखित पत्र के पैरा 3 में खिलाड़ियों के लिए निर्धारित ग्रेड के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जा सकता हैः—

(ए) 'ए' ग्रेडः

> 'ए-I '-अंतर्राष्ट्रीय, ओलंपिक, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त क्रिकेट टेस्ट मैचों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को इस श्रेणी में शामिल किया जा सकता है।
>
> 'ए-II '-केवल वे खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों और खेलों में भाग लिया हो। ओलंपिक संघ या मैत्रीपूर्ण टेस्ट मैच, जिनमें कम से कम चार या पांच देशों की टीमों ने भाग लिया है, को ग्रेड ए-II का प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।"

9. *राजेश कौशिक के मामले में* इस फैसले के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की गई थी।हालाँकि, जब उस मामले में निर्णय यू. टी. प्रशासन, चंडीगढ़ और प्रिंसिपल, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ द्वारा 25 जुलाई, 1990 के आदेश द्वारा लागू किया गया था,

तो एक एरियन जोट सिंह ने व्यथित महसूस किया और उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर *की (1990 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 11296-एरियन जोट सिंह बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़*)।उस रिट याचिका को 14 नवंबर, 1990 को न्यायमूर्ति जी. सी. मित्तल और जी. एस. चहल की मोशन पीठ द्वारा सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था।इस रिट याचिका के खारिज होने के खिलाफ, अमन जोट सिंह ने 1990 का एस. एल. *पी.* सं. 15156 दायर किया, जिसे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय *ने सीमित अवधि* में खारिज कर दिया था।इस प्रकार राजेश कौशिक के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के एकल पीठ के निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है।यह *अंतिम स्थिति होने* के कारण, यह मामला अन्तिमता हो गया है और राजेश कौशिक के मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश प्रतिवादी के लिए बाध्यकारी हैं।इसलिए, जहां तक खिलाड़ियों/महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियों को वर्गीकृत करके उनकी श्रेणीकरण *का संबंध है,* प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे राजेश कौशिक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पहले से जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करें और तदनुसार खिलाड़ियों/महिला खिलाड़ियों के लिए आरक्षित कोटे के खिलाफ सीटों पर प्रवेश करें।

10. यह हमें याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता की पहली तीन दलीलों पर लाता है जो हालांकि परस्पर निर्भर हैं, फिर भी सीरियटिम के *साथ* निपटाए जा रहे हैं।पहले विवाद की सराहना करने के लिए, यह प्रासंगिक होगा कि लगभग एक दशक पहले, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ में खिलाड़ियों/खिलाड़ियों के लिए सीटों का कोई आरक्षण नहीं था।चंडीगढ़ प्रशासन ने 19 मई, 1982 को अपने निर्णय द्वारा योग्यता परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर कुछ महत्व देने का निर्णय लिया था।कुछ साल बाद, 25 जनवरी, 1984 को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एन. सी. सी., एन. एस. एस. आदि गतिविधियों के लिए 1 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत और 5 प्रतिशत अंकों का वेटेज बंद कर दिया जाएगा और भारत सरकार की नीति के अनुसार खिलाड़ियों के लिए 1 प्रतिशत और विकलांग व्यक्तियों के लिए 1 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। यह प्रथा लगभग पाँच वर्षों तक जारी रही, जब तक राजेश कौशिक 1989 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 10022 को दर्ज करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया, क्योंकि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित सीट के खिलाफ चार वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश से उन्हें इस आधार पर इनकार कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता ग्रेड ए-I का प्राप्तकर्ता नहीं था और इसके बजायक्रिकेट के खेल में उन्हें ग्रेड बी-II सम्मानित किया गया था। राजेश कौशिक ने तर्क दिया कि चूंकि क्रिकेट के खेल में कोई प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान नहीं था और केवल विजेता और उपविजेता थे, इसलिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा अपनाई गई ग्रेडिंग मनमाना थी और उनके प्रदर्शन के आधार पर, वह ग्रेड ए खेल प्रमाण पत्र के अनुदान के हकदार थे।उस दावे के लिए, राजेश कौशिक ने पंजाब विश्वविद्यालय के निर्देशों पर भरोसा किया क्योंकि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ द्वारा कोई अलग ग्रेडिंग मानदंड या

पैटर्न निर्धारित नहीं किया गया था।राजेश कौशिक के मामले में प्रतिवादी ने यह दलील देते हुए अपनी कार्रवाई को सही ठहराने की मांग की कि चूंकि कॉलेज केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रण में था, इसलिए किसी अन्य राज्य या प्राधिकरण द्वारा उस विषय के लिए जारी किए गए निर्देश कॉलेज पर लागू नहीं थे। इस न्यायालय द्वारा 1990 (5) एस. एल. आर. 658 के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायाधीशालय द्वारा निर्णय के लिए प्रश्न यह नहीं था कि खेलों में श्रेणीकरण के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए कौन सा सक्षम प्राधिकारी था, बल्कि यह था कि क्या अपनाया गया मानदंड प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष खेल के सिद्धांतों के अनुसार था और उस वास्तविक उद्देश्य को बढ़ावा देने की मांग की गई थी जिसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटें उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित थीं।पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा अपनाए गए श्रेणीकरण के सिद्धांत को बरकरार रखते हुए, जो 'उत्कृष्ट' और 'ए' ग्रेड के अनुदान से संबंधित है, अदालत ने पाया कि अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में पंजाब विश्वविद्यालय की टीमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्रेड 'बी' के रूप में ग्रेडिंग तर्कहीन और मनमाना था। परिणामस्वरूप, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ को खिलाड़ियों की श्रेणीकरण के लिए उनके मानदंडों को संशोधित करने और उसी खेल श्रेणीकरण को अपनाने का निर्देश दिया गया जो गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज, लुधियाना जैसे अन्य संस्थानों में अपनाया गया था।

11. ओलंपिक खेलों/विश्व खेलों/राष्ट्रमंडल खेलों/विश्व कप टूर्नामेंट/एशियाई खेलों, और राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/अंतर-क्षेत्रीय टूर्नामेंट/पूर्व-एशियाई खेलों के साथ-साथ अंतर-प्रत्यावर्तन टूर्नामेंट आदि में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के श्रेणीकरण के उद्देश्य से पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ द्वारा एक समान और सामान्य श्रेणीकरण पैटर्न की इच्छा व्यक्त की गई और इसे अपनाने का निर्देश दिया गया।जहाँ तक चंडीगढ़ प्रशासन खिलाड़ियों के लिए सीटें आरक्षित करने का निर्णय है या इसके बजाय संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के ऊपर कुछ प्रतिशत अंकों का वेटेज देने का संबंध था, याचिका में न तो कोई चुनौती दी गई थी और न ही राजेश कौशिक के मामले (उपरोक्त) में कोई निर्णय या राय व्यक्त की गई थी।

12. चूंकि राजेश कौशिक के मामले में एकल पीठ के फैसले को पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा जा चुका है, इसलिए इसमें जारी किया गया श्रेणीकरण के समान स्वरूप को अपनाने का निर्देश चंडीगढ़ प्रशासन के साथ-साथ उनके द्वारा संचालित पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ के लिए भी बाध्यकारी हो जाता है। लेकिन, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क-कि *राजेश कौशिक के* मामले में इस अदालत ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और चंडीगढ़ प्रशासन को खिलाड़ियों के लिए एक निश्चित संख्या में सीटें आरक्षित करने और संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन पर वेटेज देने के मानदंडों को समाप्त करने का भी निर्देश दिया था, पूरी तरह से गलत है।दोहराने की कीमत पर, यह उल्लेख किया जा *सकता है कि* राजेश कौशिक के मामले में

निर्णय केवल क्रिकेट के खेल से संबंधित था और वह भी ग्रेड ए-I के बजाय ग्रेड बी-II प्रमाण पत्र की श्रेणी में मनमानेपन के संबंध में और यह भी निर्धारित नहीं किया गया था कि चंडीगढ़ प्रशासन या पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ द्वारा अपनाए गए मानदंड, खिलाड़ी/खिलाड़ी महिला होने के नाते प्रवेश की मांग करने वाले उम्मीदवारों को वेटेज देने के संबंध में किसी भी तरह से अवैध या मनमाना था।इस मामले पर राय व्यक्त करने न तो कोई अवसर था और न ही कोई आवश्यकता थी।

13. वास्तव में, जहां तक पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर में निहित पंजाब विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों की प्रयोज्यता का संबंध है, विद्वान कोरमेसी का तर्क बिना किसी आधार के है।पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 की खंड 27 में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए आवेदन करने वाला कॉलेज विश्वविद्यालय के सिंडिकेट द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों को पूरा करेगा।ये शर्तें नियमित रूप से गठित शासी निकाय, योग्य कर्मचारी, पर्याप्त भवन और छात्रों के रहने और रहने की अन्य सुविधाओं, पुस्तकालय, उचित शैक्षिक सुविधाओं आदि की आवश्यकता से संबंधित हैं। उस अधिनियम की खंड 30 के तहत कुछ शर्तों पर महाविद्यालय की संबद्धता समाप्त करने का भी प्रावधान किया गया है।खंड 31 के तहत, सीनेट को ऐसे विनियम बनाने की जो कर्मचारियों की नियुक्ति और अनुसरण किए जाने वाले अध्ययन के पाठ्यक्रमों को निर्धारित करने और उम्मीदवारों के लिए विश्वविद्यालय परीक्षाएं, डिग्री, डिप्लोमा आदि के लिए शर्तें निर्धारित करने के लिए शक्ति दी गई है । धारा 27 और 31 में निहित उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में संबद्धता आदि के लिए शर्तों को निर्धारित करते हुए विस्तृत विनियम बनाए गए हैं, लेकिन खिलाड़ियों/खिलाड़ियों के लिए सीटों के आरक्षण या मान्यता प्राप्त कॉलेजों में प्रवेश के समय उन्हें महत्व देने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

14. इसलिए, यह तर्क कि केवल इसलिए कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़, पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध है, यह छात्रों के दाखिले के लिए अपने मानदंड निर्धारित नहीं कर सकता है और चंडीगढ़ प्रशासन के शिक्षा और तकनीकी विभागों के नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य नहीं कर सकता, पूरी तरह से बिना किसी आधार के है।किसी भी कल्पना के बिना, एक विश्वविद्यालय राज्य द्वारा संबद्ध कॉलेजों को यह निर्देश देने की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकता है कि खिलाड़ियों/खिलाड़ियों के लिए इतनी सीटें आरक्षित की जाएंगी और यदि ऐसा नहीं किया गया तो संबद्धता को वापस लिया जा सकता है और निर्देशों का पालन न करने के कारण संस्थान को असंबद्ध कर दिया जा सकता है। निस्संदेह, एक विश्वविद्यालय, उस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसके तहत उसका गठन किया गया है, पाठ्यक्रम, अध्ययन के पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, परीक्षा के पाठ्यक्रम, अवधि, सेमेस्टर आदि से संबंधित मामलों से निपट सकता है, लेकिन किसी भी कल्पना के बिना, एक विश्वविद्यालय राज्य द्वारा संबद्ध कॉलेजों को यह निर्देश देने की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकता है कि खिलाड़ियों/खिलाड़ियों के लिए इतनी सीटें

आरक्षित की जाएंगी और यदि ऐसा नहीं किया गया तो संबद्धता को वापस लिया जा सकता है और निर्देशों का पालन न करने के कारण संस्थान को असंबद्ध कर दिया जा सकता है।वास्तव में, जहां तक प्रवेश के मानदंडों के निर्धारण का संबंध है, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार और उनके द्वारा संचालित कॉलेजों की शक्ति को एक चौथाई सदी से भी पहले ही *सर्वोच्च न्यायालय* की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा *आर. चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1823* के मामले में बरकरार रखा जा चुका है।बहुमत निर्णय देते हुए, जे. सुब्बा राव ने कहा कि -

"राज्य सरकार के पास सरकार द्वारा संचालित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में योग्य छात्रों के प्रवेश के लिए एक तंत्र और मानदंड निर्धारित करने की शक्ति है और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्रबंधन की सहमति से उक्त कॉलेजों में भी "

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता ने 30 मई, 1989 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 4119 *(डॉ. आशुतोष कौशल बनाम पंजाब* राज्य और अन्य*1990 (1) एसएलआर 543)* में इस अदालत के एकल पीठ के *फैसले पर* भी *रिलायंस को रखा है, जिसे* माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके खिलाफ एस. एल. पी. को खारिज करके बरकरार रखा है।उस फैसले के आधार पर यह तर्क दिया गया है कि 1962 में तकनीकी/चिकित्सा संस्थानों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया था और डॉ. आशुतोष कौशल, जो क्रिकेट के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट खिलाड़ी थे, को इस न्यायालय द्वारा शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखे बिना खेल के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर ही प्रवेश दिया गया था।उस फैसले की बारीकी से जांच से पता चलेगा कि डॉ. आशुतोष कौशल एक उत्कृष्ट खिलाड़ी होने के साथ-साथ एक बहुत ही उच्च शैक्षणिक योग्यता के उम्मीदवार थे, जिन्होंने हर व्यवसायी परीक्षा में प्रथम श्रेणी के साथ-साथ अपने एम.बी.बी.एस. में प्रथम श्रेणी हासिल की। जिस बात ने उन्हें इस अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया, वह थी पंजाब राज्य का इस गलत धारणा के तहत कि राज्य सरकार द्वारा 11 जनवरी, 1962 को सरकार के मुख्य सचिव, पंजाब द्वारा जारी किए गए निर्देश केवल एम.बी.बी.एस. के चरण तक लाभ देने के संबंध में थे, और उसके बाद नहीं।इस न्यायालय ने कहा कि इस तरह की संकीर्ण व्याख्या के लिए कोई वारंट नहीं था क्योंकि राज्य सरकार द्वारा सभी स्तरों पर खिलाड़ियों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।इसलिए, यह निर्णय याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का कुछ भी समर्थन नहीं देता है।

15. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता के अगले तर्क से निपटने के लिए कि तकनीकी कॉलेजों में प्रवेश के मामले में, खेल में उत्कृष्टता पर जोर दिया जाना चाहिए न कि शैक्षणिक योग्यता पर, यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रस्ताव अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खालिद हुसैन (नाबालिग) बनाम तमिलनाडु सरकार *के आयुक्त और* सचिव, *स्वास्थ्य विभाग, मद्रास, आदि मामले में तय* किया गया *है।इस सवाल का* जवाब देते हुए कि "क्या 'प्रतिष्ठित खिलाड़ियों' की श्रेणी से

संबंधित उम्मीदवारों एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए के चयन के लिए अपनाए जाने वाले उचित मानदंड, खेलों में प्रमुखता है, न कि अकादमिक उत्कृष्टता", तकनीकी महाविद्यालयों में दाखिले के मामले में, चयन में एक विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों में से किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए, *यह* निर्धारित करने के लिए अनिवार्य रूप से केवल शैक्षणिक योग्यता पर निर्भर होना चाहिए जैसा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने *पी. सबिता बनाम चिकित्सा शिक्षा निदेशक और अन्य 1983सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 9406* में 6 अप्रैल, 1984 को निर्णय लिया और *खालिद हुस्साम (नाबालिग) बनाम तमिलनाडु सरकार के आयुक्त और सचिव, स्वास्थ्य विभाग, मद्रास आदि,* मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया। कॉलेज के अधिकारियों के रास्ते में कठिनाई की सराहना करते हुए प्रवेश देने के मामले ने खेल में उत्कृष्टता के मुकाबले विद्या सम्बन्धी श्रेष्ठता को निम्नलिखित शब्दों में बरकरार रखाः—

“वास्तविक कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब एक से अधिक उम्मीदवार होती है, जिन्होंने खेल के अपने-अपने क्षेत्रों जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और आरक्षित सीटों की संख्या योग्य पाए गए उम्मीदवारों से कम है।वे सभी कमोबेश बराबर होने के कारण, योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जाना सबसे अच्छा तरीका है।ऐसे मामले में, चयन अनिवार्य रूप से उनकी विद्या सम्बन्धी योग्यता पर निर्भर होना चाहिए।यहां तक कि पी. *सबिता के* मामले में भी अदालत ने एक ही वर्ग के भीतर आने वाले खिलाड़ियों के बीच तुलनात्मक श्रेष्ठता का निर्णय लेने के लिए किसी भी दिशानिर्देश को निर्धारित करने में कठिनाई को महसूस किया और यह कहा गया कि जब उम्मीदवारों को खेल में समान दक्षता प्राप्त करते हुए दिखाया जाता है, तो उनकी विद्या सम्बन्धी श्रेष्ठता को उनके पक्ष में एक झुकाव कारक के रूप में सेवा में दबाया जा सकता है। चयन के उद्देश्यों के लिए किसी भी दिशानिर्देश की अनुपस्थिति में में, 'प्रतिष्ठित खिलाड़ियों' की श्रेणी के तहत आने वाले योग्य उम्मीदवारों के बीच तुलनात्मक योग्यता का निर्णय अनिवार्य रूप से होगा, जैसा कि विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कहा, उम्मीदवारों के चयन में 'व्यक्तिपरकता का एक तत्व जो मनमानेपन की शुरुआत करेगा' क्योंकि यह चुनाव करने में कार्यपालिका के विवेक पर छोड़ दिया जाएगा।किसी भी दिशानिर्देश की अनुपस्थिति में में, चयन समिति के लिए योग्यता परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के अलावा कुछ भी नहीं है।विद्वान वकील का तर्क स्पष्ट रूप से पी. सबिता के मामले की टिप्पणियों पर आधारित था कि 'प्रख्यात खिलाड़ी' श्रेणी से संबंधित एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन के मामले में अपनाई जाने वाली उचित परीक्षा खेल में सर्वोपरि थी। और अकादमिक उत्कृष्टता नहीं, स्वीकार नहीं किया जा सकता। वह परीक्षण स्पष्ट रूप से वर्तमान नियम की व्याख्या में लागू नहीं किया जा सकता है।”

उच्चतम न्यायालय के उनके अध्यक्षों द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, पंजाब-इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ द्वारा अपनाए गए मानदंडों के खिलाफ आक्षेप, कि दाखिले उम्मीदवारों के विद्या सम्बन्धी

प्रदर्शन महत्व देकर किए जाएंगे, खारिज किए जाने के योग्य हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से उचित और न्यायसंगत है।

16. अब तक 1 का अंतिम विवाद यह है कि *रणबीर सिंह बनाम थापर इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला और एक अन्य,* में इस न्यायालय की खण्ड *पीठ (जिसमें* आर. *एन. मित्तल, जे. और एम. एम. पुंछी,* माननीय न्यायाधीश - जो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत हैं) का निर्णय सही कानून नहीं बताता है और *मिस मनिंदर कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य,* इस अदालत के एकल पीठ के फैसले को गलत *तरीके से खारिज कर* दिया *है*यह ध्यान दिया जा सकता है कि रणबीर सिंह के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के उनके आधिपत्य द्वारा लिया गया दृष्टिकोण खालिद हुसैन के मामले (सुप्रा) द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से सुसंगत है और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता की तुलना में विद्या सम्बन्धी क्षेत्र में उत्कृष्टता पर जोर देने को उनके आधिपत्य द्वारा प्राथमिकता दी गई थी। जैसा कि यहां प्रस्तुत किए गए निर्णय के समापन पैरा से स्पष्ट होगाः—

"ऐसे महाविद्यालयों में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवार का विद्या सम्बन्धी जीवन अच्छा होना चाहिए, अन्यथा उसके लिए इसे उत्तीर्ण करना संभव नहीं हो सकता है।यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने में असमर्थ छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।यदि खंड की जांच इस दृष्टिकोण से की जाती है, तो इसे तर्कहीन और मनमाना नहीं कहा जा सकता है।"

वास्तव में, रणबीर सिंह के मामले (ऊपर) में इस अदालत की खण्ड *पीठ के* उनके आधिपत्य द्वारा वही दृष्टिकोण अपनाया जो बाद में खालिद हुसैन के मामले (ऊपर) में माननीय *सर्वोच्च न्यायालय द्वारा* लिया गया था।इसलिए, रणबीर सिंह के मामले (ऊपर) में खण्ड *पीठ द्वारा लिए* गए विचार को बरकरार रखा जाता है।

17. परिणामतः, ऊपर दर्ज किए गए इन कारणों के लिए, प्रतिवादी द्वारा अपनाए गए मानदंडों के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया जाता है।वास्तव में, इन कारणों को ध्यान में रखते हुए और मामले को वास्तविक तात्कालिकता के रूप में देखते हुए, हमने 5 सितंबर, 1991 को ही निम्नलिखित आदेश की घोषणा करके इन याचिकाओं का निपटारा कियाः—

"बाद में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करके 1991 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 11995,10758,12052 और 12072 का निपटारा करते हैंः—

1. जहाँ तक उत्तरदाताओं केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ द्वारा अपने विवरण-पुस्तिका में, खिलाड़ियों/खिलाड़ियों-महिलाओं के लिए निर्धारित आरक्षित श्रेणी के तहत बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को दिए गए वेटेज के संबंध में निर्धारित मानदंडों को चुनौती दी गई है- इसे खारिज

कर दिया गया है और हम 1991-92 सत्र के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा प्रकाशित अपने विवरण-पुस्तिका में प्रतिवादी द्वारा निर्धारित मानदंडों को बनाए रखते हैं।

2. जहां तक खिलाड़ियों/खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों को वर्गीकृत करके श्रेणीकरण देने का सवाल है, उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे *राजेश कौशिक बनाम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ और अन्य* के मामले में जो इस न्यायालय द्वारा 30 मई, 1990 को तय किया गया था पहले से जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करें। , और तदनुसार खिलाड़ियों/खिलाड़ियों के लिए आरक्षित कोटे के अंतर्गत सीटों पर प्रवेश देना; और

3.जहां तक आरक्षित श्रेणी के खिलाड़ियों/महिलाओं के खिलाफ प्रवेश के उद्देश्यों के लिए 'निशानेबाजी' के खेल/अनुशासन को शामिल नहीं करने के खिलाफ शिकायत का संबंध है, हम इसे पहली बार में पूर्ण पीठ द्वारा निर्णय का विषय नहीं मानते हैं और इस कारण से, निर्देश देते हैं कि 1991 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 10758 (निश्चल गुप्ता बनाम यू. टी. *चंडीगढ़ और अन्य) को 11 सितंबर, 1991* को निर्णय के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए, जो सूची में सबसे ऊपर रखा जाए। और

4. इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में खेल श्रेणी में सीटों का आवंटन प्रत्येक शाखा में सीटों का 5 प्रतिशत का अंश या पूर्णांक करना होगा।यदि किसी भी शाखा में खेल श्रेणी की कोई भी सीट खाली रहती है, तो इसे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए खुला रखा जाएगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।"

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियंका वर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा